NEETU SINGH COMPUTER AWARENESS

KD Publication

NEETU SINGH

Computer Awareness

Concepts with Theory & PYQs

- ☑ Chapterwise Theory with Concepts
- ☑ Chapterwise Question Bank
- ☑ All PYQs of SSC (Pre + Mains), Railway & Delhi Police

Useful for

SSC (CGL/CHSL/CPO/STENO./MTS/GD), BANK, RAILWAY, POLICE & OTHER COMPETITIVE EXAMS

Neetu Singh

SCAN करें और सीधे जुड़े हमारे Channels से और सुनिश्चित करें अपनी सफलता!

KD LIVE

GOLDEN BOOK SOLVED BY NEETU SINGH

GOLDEN BOOK

SSC ENGLISH

With Exclusive!

GOLDEN RULES

247

SOLVED PAPERS

2016 - Till Date

SOLVED BY NEETU SINGH

PAPERS COVERED

- CGL (TIER-I, 2016-2022)
- CHSL (TIER-I, 2022)
- CGL (TIER-II,2022)
- CHSL (TIER-II,2022)

Useful for

SSC (CGL/CHSL/CPO/STENO./MTS/GD), BANK, NDA, CDS, & OTHER COMPETITIVE EXAMS

With VIDEO SOLUTIONS

KD Publication

Neetu Singh

CURRENT AFFAIRS

June - 2024

By Anu Ma'am

9555108888/9555208888

8586903756/8586903746

Q. डॉ. के. कस्तूरीरंगन को निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था ?/Dr. K. Kasturirangan was made the Chairman of which of the following committees?

a) राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए
Draft National Water Policy

b) व्यापार-वाणिज्य से संबंधित नीति-निर्माण हेतु
For policy making related to trade and commerce

c) राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020
National Education Policy- 2020

d) विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जॉच हेतु
Judicial inquiry into Vikas Dubey case

Dr K. Kasturirangan Committee submits the Draft National Education Policy to the Union HRD Minister

The Committee led by the Chairman Dr. Kasturirangan submitted the Draft National Educational Policy to the Union Human Resource Development Minister, Shri Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ and Minister of State for HRD, Shri Sanjay Shamrao Dhotre in New Delhi today in the presence of Shri R. Subrahmanyam, Secretary Department of Higher Education and Smt. Rina Ray, Secretary Department of School Education & Literacy and other senior officials of the Ministry.

Q. एक राष्ट्र, एक चुनाव' के संबंध में गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ?/**Who has been made the chairman of the committee formed on 'One Nation, One Election'?**

a) रामनाथ कोविंद (पूर्व राष्ट्रपति)
Ram Nath Kovind (Former President)

b) अधीर रंजन चौधरी
Adhir Ranjan Chowdhury

c) एनके सिंह / N.K. Singh

d) संजय कोठारी / Sanjay Kothari

Q. चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

Who has been appointed as the Chairman of Cheetah Project Steering Committee?

a) पीआर सिन्हा / P.R. Sinha
b) एचएस नेगी / HS Negi
c) पीके मलिक / PK Malik
d) राजेश गोपाल / Rajesh Gopal

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है, और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पिछले दो महीनों में स्थानांतरण परियोजना के हिस्से के रूप में लाए गए छह चीतों की मृत्यु के बाद लिया गया था। अन्य 10 सदस्यों में राजस्थान के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरएन मेहरोत्रा; पीआर सिन्हा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक; एचएस नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ, वन्यजीव; और पीके मलिक, डब्ल्यूआईआई में पूर्व संकाय।

जीएस रावत, डब्ल्यूआईआई के पूर्व डीन; मित्तल पटेल, अहमदाबाद स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता; कमर कुरैशी, डब्ल्यूआईआई वैज्ञानिक और एनटीसीए के महानिरीक्षक; और एमपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव वार्डन अन्य सदस्य हैं।

Q. मणिपुर हिंसा की जाँच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ?

Who has been appointed as the chairman of the committee formed to investigate the Manipur violence?

a) राजेश भूषण / Rajesh Bhushan
b) अजय लांबा / Ajay Lamba
c) आर. एस. शर्मा / R.S. Sharma
d) के. वी. कामथ / K.V. Kamath

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है. आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे. जबकि रिटायर्ड IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड IPS ऑफिसर आलोक प्रभाकर इस समिति के सदस्य होंगे.

मणिपुर हिंसा के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी. साथ ही कोई भी शख्स पर्याप्त सबूत के आधार पर अपनी शिकायत इस आयोग में दर्ज करा सकता है.आयोग इन बिंदुओं पर अपनी जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी और कैसे स्थिति बद से बदतर होती चली गई? आयोग इस बात की भी जांच करेगा हिंसा के वक्त जो सरकारी कर्मचारी या जिम्मेदार लोग थे उस वक्त क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई या फिर उनकी भूमिका उस वक्त कैसी थी. इस आयोग का हेड क्वार्टर इंफाल में होगा. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह से अपील की है कि इंफाल-दीमापुर NH-2 हाईवे पर लगे अवरोधों को हटा लें.

Q. पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ? / **Who has been made the chairman of the committee on prevention of stubble burning?**

a) मदन बी. लोकुर / Madan B. Lokur
b) राजीव कुमार / Rajiv Kumar
c) आर. एस. शर्मा / R.S. Sharma
d) शशि शेखर वेम्पति / Shashi Shekhar Vempati

SC puts on hold order appointing Justice Madan Lokur to head panel to prevent stubble-burning

Solicitor General Tushar Mehta informs Bench that a new law may come out in the next few days that proposes to have a permanent body to deal with stubble-burning.

October 26, 2020 03:12 pm | Updated 11:14 pm IST - NEW DELHI:

KRISHNADAS RAJAGOPAL

READ LATER PRINT

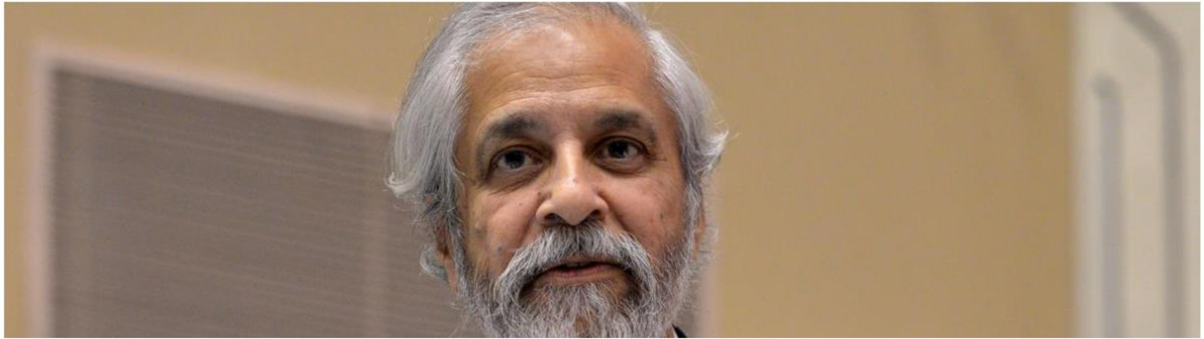

Q. सुरजीत भल्ला समिति का संबंध निम्न में से किससे है ?/**Surjit Bhalla Committee is related to which of the following?**

a) सरकारी आंकड़ो मे राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु
To prevent political interference in government data

b) ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार हेतु
To improve the drug regulatory system

c) व्यापार-वाणिज्य से संबंधित नीति-निर्माण हेतु
For policy making related to trade and commerce

d) इनमे से कोई नहीं / None of them

High Level Advisory Group (HLAG) headed by Dr. Surjit S. Bhalla has been constituted by the Department of Commerce. The HLAG has made several recommendations for boosting India's share and importance in global merchandise and services trade. Among other things, the Report identifies tax reforms also to boost export and investment channels for exports.

The Committee has recommended "Elephant Bonds" as a specialised security product providing funds towards Long Term Infrastructure.

HLAG has also made recommendations for reforms in Financial Services Framework for making India a Preferred Destination for financial services.

This was stated by the Union Minister of Finance & Corporate Affairs,Smt. Nirmala Sitharamanin a written reply to a Parliament Question in Rajya Sabha today.

Q. निम्नलिखित में से कौंन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित जेबीपी समिति का सदस्य नहीं था ?

Who among the following was not a member of the JBP Committee constituted for reorganisation of states on linguistic basis?

a) सरदार वल्लभभाई पटेल / **Sardar Vallabhbhai Patel**
b) जवाहर लाल नेहरू / **Jawaharlal Nehru**
c) पट्टाभि सीतारमैया / **Pattabhi Sitaramayya**
d) जयशंकर प्रसाद / **Jaishankar Prasad**

KD Campus

Q. Which of the following committees was formed to propors ও roadmap to double the income of formers by the year 2022

वर्ष 2022 तक किसानो की आय को दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था ?

A. अशोक दलवई समिति / Ashok Dalwai Committee

B. जस्टिस लोढ़ा समिति / Lodha Committee

C. कस्तूरी रंगन समिति / Kasturi Rangan Committee

D. इनमें से कोई नही / None of these

समिति की रिपोर्ट से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 13 अप्रैल 2016 को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।
- इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य। इस सामरिक ढाँचे में चार चिंताएँ भी थी जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुनः मज़बूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी ज़ोर दिया गया था, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2002-03 से 2012-13 और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रति वर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई।
- अतः किसानों की दोगुनी आय से तात्पर्य तीन गुने प्रयास और संसाधनों से है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2011-12 की कीमतों पर लगभग 6,40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाए और इसमें कृषि रसद, कोल्ड चेन्स आदि में किये गए निवेश को शामिल नहीं किया जा सकता।
- इस निवेश का 80% सरकार द्वारा प्राप्त होगा। यदि दोगुनी किसान आय के सपने को वास्तविक रूप प्रदान करना है तो कृषि के लिये निवेश में 22% तक की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

Q. Who has been made the chairman of the committes on prevention of stubble burning?
पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ?

A. मदन बी. लोकुर / Madan B. Lokur
B. राजीव कुमार / Rajiv Kumar
C. आर. एस. शर्मा / RS. Sharma
D. शशि शेखर वेम्पति / Shashi Shekhar Vempati

नयी दिल्ली,16 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब ,हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक संबंधी कदम उठाने के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति शुक्रवार को गठित की। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने समिति के सहयोग के लिए राष्ट्रीय कैडट कोर(एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की तैनाती के निर्देश दिए साथ ही समिति के गठन पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित राज्यों की दलीलें सुनी जा चुकी हैं। न्यायालय ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) तथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को उन खेतों की निगरानी में लोकुर समिति की मदद करने का निर्देश दिया जिनमें पराली जलाई जाती है। पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी

Q. What is the noms of the committes formed to recover money from Jefoulters?

डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है ?

A. प्रणव सेन समिति / Pranab Sen Committee

B. प्रदीप नंदराजोग समिति / Pradeep Nandrajog

C. एआर दवे समिति / AR Dave Committee

D. मिहिरशाह समिति / Mihir Shah Committee

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनएसईएल के बकाएदारों से पैसा वसूलने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग के नेतृत्व में एक समिति के गठन का आदेश दिया।

Advertisement

इस कदम से डिफॉल्टरों से तेज गति से वसूली सुनिश्चित होगी। वसूली के बाद, एससी द्वारा नियुक्त समिति को दावों के सत्यापन के बाद बिक्री आय का समान वितरण करने का अधिकार है।

Q. Who is associated with the committes formed to draft the National Water Policy?
राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का संबंध किससे है ?

A. मिहिरशाह समिति / Mihir Shah Committee
B. सुरजीत भल्ला समिति / Surjit Bhalla Committee
C. प्रणव सेन समिति / Pranab Sen Committee
D. इनमें से कोई नहीं। None of these

A committee has been constituted under the chairmanship of Mihir Shah to prepare the draft National Water Policy by the Union Jal Shakti Ministry.
Mihir Shah is a former member of the Planning Commission and an expert in the field of water conservation.

(National Water Policy):
After independence, three national water policies have been formulated in the country.
The first, second and third National Water Policy were formulated in the years 1987, 2002 and 2012 respectively.
In the National Water Policy, water is considered as a natural resource and the basis of life, livelihood, food security and sustainable development.

Q. Who hos boon appointed as the chairman of the empowered ponsl constituted for COVID-19 vaccine?
कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ?

A. राजेश भूषण / Rajesh Bhushan
B. प्रणव सेन / Pranab Sen
C. आर. एस. शर्मा / RS. Sharma
D. मुकुंदकम शर्मा / Mukundakam Sharma

RS Sharma, former Trai chief, to head empowered panel for Covid-19 vaccine

Sharma was the first person to officially initiate a discussion on vaccination delivery in the government in the summer of 2020 when Covid-19 cases peaked

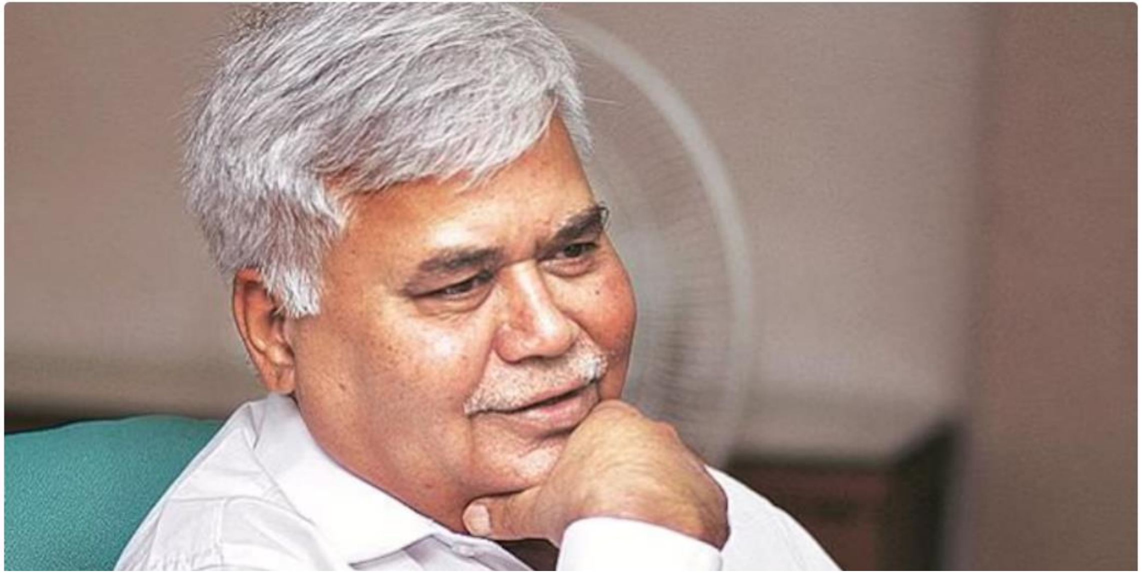

Q. जीएसटी रिर्टन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ?

Who has been made the chairman of the committee formed to simplify the process of GST returns?

a) राजेश भूषण / **Rajesh Bhushan**

b) अजय भूषण पांडे / **Ajay Bhushan Pandey**

c) अरविन्द पानगडिया / **Arvind Panagariya**

d) एस. सी. दास / **S.C. Das**

जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने के लिए समिति गठित

भाषा • 21 Nov 2017, 7:40 pm

Subscribe YouTube 10M

नयी दिल्ली, 21 नवंबर भाषा सरकार ने जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में आज एक समिति गठित की जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी।

Q. ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ? / **Who has been made the chairman of the committee formed to tackle industrial pollution around Taj Mahal?**

a) राजनाथ सिंह / **Rajnath Singh**
b) प्रणव सेन / **Pranab Sen**
c) के. वी. कामथ / **K.V. Kamath**
d) सी. के. मिश्रा / **C.K. Mishra**

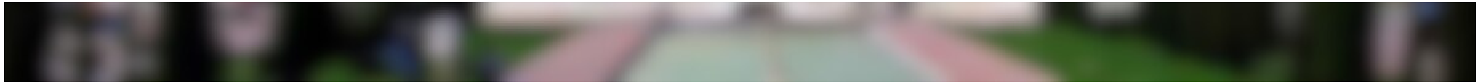

नई दिल्ली: सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों नीरी, आईआईटी और विभिन्न अन्य मंचों के विशेषज्ञों को लेकर एक समिति का गठन किया है जो ताज महल के आस - पास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखेगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बताया कि समिति की अध्यक्षता पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा करेंगे.

Q. सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था?

When was Sarkaria Commission formed?

a) 1988

b) 1986

c) 1983

d) 1982

KD Campus

Q. रघुराम राजन समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
Raghuram Rajan Committee is related to which of the following?

a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित
Related to Regional Rural Banks

b) खनिज तेल में सुधार से संबंधित
Related to improvement in mineral oil

c) कृषि जोत कर से संबंधित
Related to agricultural land tax

d) वित्तीय क्षेत्र संबंधित सुधार
Financial Sector Related Reforms

Q. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है ? / **Which committee is related to the three-tier Panchayati Raj system?**

a) अशोक मेहता समिति
Ashok Mehta Committee

b) बलवंत राय मेहता समिति
Balwant Rai Mehta Committee

c) सरदार स्वर्ण सिंह समिति
Sardar Swaran Singh Committee

d) एल. एम. सिंघवी समिति
L.M. Singhvi Committee

Balwant Rai Mehta Committee

Ashok Mehta Committee

G V K Rao Committee

L M Singhvi Committee

Q. रंगराजन समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
Rangarajan Committee is related to which of the following?

a) गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा
Review of poverty measurement methodology

b) बैंकिग सुधार / Banking Reforms

c) कर सुधार / Tax reforms

d) बेरोजगारी से संबंधित
Related to unemployment

Q. फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है?

Fazal Ali Commission is related to which of the following?

a) आर्थिक विकास से / Economic growth

b) आरक्षण से / By reservation

c) राज्यों के पुनर्गठन से Reorganisation of States

d) इनमें से कोई नही / None of these

Q. मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में सिफारिश करने से संबंधित समिति कौंन सी है ? / **Which is the committee to make recommendations on fundamental duties?**

a) अशोक मेहता समिति / Ashok Mehta Committee

b) सरदार स्वर्ण सिंह समिति
Sardar Swaran Singh Committee

c) कपूर समिति / Kapoor Committee

d) के. संथानम समिति / K. Santhanam Committee

Fundamental duties were recommended by **Sardar Swarn Singh committee.**

These were incorporated in Part IV-A of the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 on the recommendations of the Swaran Singh Committee.
Originally 10 in number, one more duty was added through the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
All the eleven duties are listed in Article 51-A of the Constitution (the sole Article in Part-IV-A).

Q. निम्न में से कौन सा शिक्षा से संबंधित एक आयोग है ?

Which of the following is a commission related to education?

a) गाडगिल आयोग / Gadgil Commission
b) मेहता आयोग / Mehta Commission
c) कोठारी आयोग / Kothari Commission
d) इनमे से कोई नहीं / None of these

Arun Goel Committee
To strengthen the Capital Goods(CG) Sector and contribute more actively in the national goal of achieving a USD 5 trillion economy and a USD 1 trillion manufacturing sector

Radha Krishnan Commission (1948)-Establishment of the University Grant Commission

K. Santhanam Committee-- Establishment of CVC

Shivaraman Committee (1979)--Establishment of NABARD

Injeti Srinivas Committee--- Corporate Social Responsibility (CSR)

Punchhi Commission-- Centre-State relations

Nehru Report (1928):
Proposed constitutional reforms for India, aiming at self-governance and a federal structure.
Dhar Commission (1948):
Investigated the Jallianwala Bagh massacre and recommended actions against General Dyer.
Shah Commission (1977):
Inquired into excesses committed during the Emergency (1975-1977) and recommended actions against those responsible.
Mandal Commission (1979):
Examined the social and economic backwardness of various castes and communities to recommend quotas in public services.

नेहरू रिपोर्ट (1928):
भारत के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सुधार, जिसका लक्ष्य स्वशासन और एक संघीय ढांचा है।
धार आयोग (1948):
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की और जनरल डायर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।
शाह आयोग (1977):
आपातकाल (1975-1977) के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।
मंडल आयोग (1979):
सार्वजनिक सेवाओं में कोटा की सिफारिश करने के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच की गई।

Kelkar Committee (2002):
Suggested reforms in direct and indirect taxes in India.

केलकर समिति (2002):
भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार का सुझाव दिया।

N.K. Singh Committee (2003):
Formulated guidelines for fiscal responsibility and budget management.

एन.के. सिंह समिति (2003):
राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए।

Rajinder Sachar Committee (2006):
Studied the socio-economic and educational status of Muslims in India.

राजिंदर सच्चर समिति (2006):
भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया।

Tapan Ray Committee (2019):
Examined the regulatory framework for fintech companies.

तपन रे समिति (2019):
फिनटेक कंपनियों के लिए नियामक ढांचे की जांच की।

BANKING SECTOR

Nachiket Mor Committee (2014):

This committee, chaired by Nachiket Mor, was formed to examine comprehensive financial services for small businesses and low-income households.

It recommended measures to increase financial inclusion

HR Khan Committee (2015):

Led by H. R. Khan, former Deputy Governor of the RBI, this committee examined the existing framework for monetary policy in India.

It made recommendations on issues such as inflation targeting, monetary policy transmission and improving the decision-making process of the RBI's Monetary Policy Committee (MPC).

Basel Norms

The Basel Accords are 3 series of banking regulations (Basel I, II, and III) set by the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS).

Poverty Committee

VM Dandekar and N Rath Poverty Committee

Alagh Committee 1979,

Lakdawala Committee

C Rangarajan Committee on Poverty

Tendulkar Committee of Poverty Estimation2009

"**Srikrishna Committee"-** separate statehood for Telangana.

KD LIVE

KD Campus

Current Affairs - By Anu Ma'am

DOWNLOAD PDF FROM KD LIVE APP

9555108888/9555208888

8586903756/8586903746